बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 209 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 05 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली अग्निकांड : गुरुग्राम में अग्रवाल फैमिली का एक साथ संस्कार,एक साथ जलीं 5 चिताएं... हर आंख हुई नम

गुरुग्राम/दिल्ली। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड ने हंसते-खेलते अग्रवाल परिवार को ऐसी त्रासदी दी है जिसे देख हर किसी का कलेजा कांप उठा। इस हादसे में जान गंवाने वाले गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के पांच सदस्यों का कल गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्मशान घाट पर जब एक साथ पांच चिताएं सजीं, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। हादसे में पूरे परिवार के खत्म हो जाने के कारण अग्रवाल परिवार में मुखाग्नि देने वाला कोई सीधा वारिस नहीं बचा था। ऐसे में बेहद भारी मन से दूर के रिश्तेदारों और सगे-संबंधियों ने एक साथ पांचों चिताओं को मुखाग्नि दी।

दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान- मृतकों के परिजनों को 10 लाख और गंभीर घायलों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने की दुखद घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये और इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि (मुआवज़ा) की घोषणा की। एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साकेत स्थित मैक्स अस्पताल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने आग में घायल हुए लोगों से मुलाक़ात की और उनके इलाज की समीक्षा की। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने घायलों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की, और अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए। एक बयान में, दिल्ली सीएमओ ने कहा, प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें सहायता के रूप में 5 लाख रुपये मिलेंगे। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि घायलों के चिकित्सा खर्चों की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन के समन्वय से की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी मरीज़ों को सर्वोत्तम संभव इलाज मिले। इसके अतिरिक्त, मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके मूल स्थानों

तक पहुँचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। बयान में आगे कहा गया, «दिल्ली सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की और इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों को संबल मिलने की प्रार्थना करते हैं।» मुआवज़े की यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब इस जानलेवा आग की घटना की जाँच अभी भी जारी है। सूत्रों ने बताया कि जाँचकर्ताओं को पता चला है कि आग लगने के समय होटल की छत से बाहर निकलने का रास्ता (एग्ज़िट) बंद था, जिससे संभवतः अंदर फँसे लोगों के लिए बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण रास्ता अवरुद्ध हो गया था। दिल्ली पुलिस ने इस घटना की जाँच के लिए 10 टीमें गठित की हैं, जिनमें से पाँच टीमों को होटल के फ़रार मैनेजर जय मिश्रा का पता लगाने का काम सौंपा गया है। जाँचकर्ता एक ऐसे मुख्य चश्मदीद गवाह की भी तलाश कर रहे हैं, जिसकी गवाही से आग लगने की घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। पूछताछ के दौरान, होटल के मालिक लवकेश बजाज ने खुलासा किया कि उनके पास तीन हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज़ हैं लेमन ग्रीन, मिकासा और फ़्लोरिश स्टे। सूत्रों के अनुसार, इनमें से दो प्रतिष्ठान उनकी निजी संपत्ति हैं, जबकि मिकासा में वे तीन अन्य व्यक्तियों के साथ साझीदार हैं। इस दुखद घटना में कई लोगों की जान चली गई, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। पुलिस ने घटना में मारे गए 12 विदेशी नागरिकों में से नौ की पहचान कर ली है और उनके शवों को उनके संबंधित देशों में वापस भेजने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ उनका विवरण साझा किया है। इस बीच,एम्स में शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि अब तक छह शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने कहा कि मृत्यु का सटीक कारण जांच और फोरेंसिक विश्लेषण पूरा होने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि, शुरुआती जांच से पता चलता है कि ज़्यादातर पीड़ितों की मौत धुएं में सांस लेने से हुई घुटन के कारण हुई। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक टीम के आगे की जांच के लिए घटनास्थल पर दोबारा जाने की उम्मीद है, क्योंकि अधिकारी आग लगने के सटीक कारण का पता लगाने और इस दुखद घटना में योगदान देने वाली किसी भी चूक की पहचान करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं।

दिल्ली-एनसीआर की तूफानी बारिश- 80-100 किमी प्रति घंटा की हवा! कई जगह गिरे पेड़; जहां-तहां फंसे लोग

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश शुरू हुई। इससे पूरे शहर का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सड़कों पर वाहन फंसे रहे और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। हवा की रफ्तार इतनी थी कि कुछ जगह टीन शेड गिरने की सूचनाएं हैं।दिल्ली मौसम विभाग ने पहले आज दोपहर 2:00 बजे के आसपास दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया था। इसके साथ मध्यम गरज-चमक, बिजली और तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार जताए थे। बुराड़ी, मॉडल टाउन और करावल नगर जैसे इलाकों में ओलावृष्टि भी संभावना जताई थी। नोएडा के सेक्टर-70 में आधा दर्जन पेड़ गिर गए। कुछ पेड़ लोगों के वाहनों पर गिर गए, जिससे उनको काफी नुकसान हो गया। साथ ही बिजली के तार टूटने से कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ ने बुधवार को दस्तक दी है। इसका असर बृहस्पतिवार दोपहर में देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार, 7, 8 और 9 जून को मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने का अनुमान है। इससे तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। ऐसे में गर्मी बढ़ेगी। दूसरी ओर, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह धूप रही। इससे लोग गर्मी से परेशान दिखे। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत महसूस हुई।

पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से की बातचीत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्ष ऊर्जा सहयोग का दायरा बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति प्रभावित होने के बीच भारत अपने कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज बुधवार को भारत पहुंची थीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह यात्रा भारत और वेनेजुएला के संबंधों को और गहरा करने में मदद करेगी। जनवरी में तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी बलों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। भारत कभी वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल का प्रमुख प्रसंस्करणकर्ता था और एक वक्त में प्रतिदिन चार लाख बैरल से अधिक तेल आयात करता था। हालांकि, अमेरिका के व्यापक प्रतिबंधों और अनुपालन संबंधी जोखिमों के कारण 2020 में यह आयात लगभग बंद हो गया था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद प्रतिबंधों में ढील मिलने पर भारत ने वेनेजुएला से फिर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। हाल के सप्ताहों में भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने पश्चिम एशिया संकट के कारण वेनेजुएला से तेल आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें विदेश, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना तथा परिवहन मंत्री शामिल हैं।

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश; दिन में छाया अंधेरा

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में गुरुवार दोपहर के बाद मौसम अचानक से बदल गया। आसमान में बादल छाने के बाद तेज आंधी शुरू हो गई। जिसके बाद कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। एनसीआर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया था।

नोएडा में आंधी-तूफान और तेज बारिश से बदला मौसम

पिछले दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बाद बृहस्पतिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। दोपहर तक जहां तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग बेहाल थे, वहीं शाम होते-होते आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। दिनभर तेज धूप और उमस के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सड़कों पर निकलने वाले लोग पसीने से तरबतर नजर आए। मौसम विभाग की ओर से पहले ही मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई थी, जो शाम को सही साबित हुई। दोपहर के समय अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हुई, जिसके बाद कई इलाकों में धूलभरी आंधी आई। इसके बाद तेज बारिश और बिजली की कड़क के साथ मौसम सुहावना हो गया। बारिश शुरू होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। कई जगह लोग घरों की छतों और बालकनियों से बारिश का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया था कि दिल्ली के बुराड़ी, मॉडल टाउन और करावल नगर में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ मध्यम गरज और बिजली कड़ने के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई। वहीं 80-100 किमी/घंटा तेज तूफानी हवाओं की चेतावनी दी थी।

मौसम विभाग का अलर्ट

बीते बुधवार को मौसम विभाग ने इन दोनों दिन बारिश का यलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान तेज धूलभरी आंधी, हल्की बारिश, गरज-चमक जैसी मौसमी घटनाएं होंगी। इससे छह जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 4 से 6 जून तक बारिश होने की संभावना जताई थी। एक नए पश्चिमी विक्षोभ ने बुधवार को दस्तक दी है। इसका असर बृहस्पतिवार सुबह देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार, 7, 8 और 9 जून को मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने का अनुमान है। इससे तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। ऐसे में गर्मी बढ़ेगी।

जली हुई बदबू, बिजली के लटकते तार, मदद के लिए चीखों की डरावनी यादें - अग्निकांड के बाद दहशत में मालवीय नगर

नई दिल्ली। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के लोग गुरुवार को भी डर और सदमे में है। दरअसल, बुधवार सुबह जिस गली में फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट में आग लगी थी, वहां कुछ घंटे पहले हुई त्रासदी के निशान अभी भी बने हुए है। पुलिस बैरिकेड्स से अंदर जाने पर रोक और जांच करने वालों के जले हुए स्ट्रक्चर की तलाशी लेने के कारण, लोगों को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि उन्होंने क्या देखा था। कई लोगों के लिए, नींद आना मुश्किल था। होटल से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाने वाले एक दुकानदार ने कहा कि उन्होंने जो मंज़र देखा वह हमेशा उनकी यादों में रहेगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, जले हुए लोग, बिल्डिंग से कूदते हुए लोग, लाशें देखकर पूरी रात नींद नहीं आई। छोटी सी आवाज़ से भी डर लग रहा था। एक और रहने वाले कन्हैया ने कहा कि इस हादसे ने न सिर्फ़ उन परिवारों को सदमा दिया है जिन्होंने अपनों को खो दिया, बल्कि आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी। उन्होंने कहा, बच्चे पूछ रहे हैं कि यहां क्या हुआ। मेरी पत्नी रात भर सो नहीं पाई, और कहा कि फंसे हुए मेहमानों की चीखें और रोने की आवाज़ें रहने वालों के कानों में गूंज रही हैं। उन्होंने कहा, जब भी हम इस गली से गुज़रेंगे, ये यादें ताज़ा हो जाएंगी। हम उन चीखों को कभी नहीं भूल सकते। गुरुवार को होटल के आस-पास का इलाका बंद रहा क्योंकि दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमों ने मौके की जांच की। लोग बैरिकेड्स के पास जमा हो गए, उस भयानक सुबह के बारे में बातें कर रहे थे और कभी-कभी काली पड़ चुकी बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इलाके को एहतियात के तौर पर सील कर दिया गया था ताकि स्ट्रक्चरल असेसमेंट और सबूत इकट्ठा करने में आसानी हो।

इन्वेस्टिगेटर उन घटनाओं के क्रम को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से हाल के सालों में नेशनल कैपिटल में आग लगने की यह सबसे भयानक घटना हुई। पुलिस जांच के तहत लोगों, दुकानदारों, होटल कर्मचारियों और दूसरे गवाहों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर गैर-इरादतन हत्या समेत कई आरोप लगाए हैं। पूछताछ के दौरान, बजाज ने कथित तौर पर इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उन्होंने 2022 में बिल्डिंग खरीदी थी और वहां एक होटल-कम-गेस्ट हाउस चला रहे थे।

पुलिस जगह के लिए मिली परमिशन और लाइसेंस के बारे में उनके दावों को वेरिफाई कर रही है। इन्वेस्टिगेटर होटल मैनेजर जय मिश्रा की भी तलाश कर रहे हैं, जो पुलिस के मुताबिक, होटल के रोज़ाना के काम संभाल रहे थे। पुलिस ने कहा कि होटल के पास कथित तौर पर सिर्फ़ छह कमरों की परमिशन थी, लेकिन वह करीब 25 कमरे चला रहा था। जब जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या गलत हुआ, तो लोगों को उस सुबह की यादें सता रही हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि उसने इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। मालवीय नगर में कई लोगों के लिए, आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन उसके पीछे छोड़ा गया डर अभी भी सुलग रहा है।

साख का सवाल

पहले नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने और फिर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानि सीबीएसई की बारहवीं परीक्षा के नतीजों को लेकर ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) यानि मूल्यांकन प्रणाली ही सवालों के घेरे में आ गई थी। परीक्षा देने वाले छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश बढ़ रहा था। सीबीएसई ने छात्रों को री-इवैल्यूएशन का विकल्प दिया था लेकिन देशभर में सीबीएसई का पोर्टल 20 घंटे ठप्प रहने के बाद जब खुला तब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इससे छात्रों में गुस्से को और बढ़ा दिया। इन सारे घटनाक्रमों ने सीबीएसई की साख को जमीन पर ला दिया और छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा ही उठ गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए हस्तक्षेप किया और केन्द्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर उनकी जगह लोकेश प्रशांत सौतराम को अध्यक्ष और वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एस. राधा चौहान के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जो ओएसएम सर्विस खरीद की टैंडर प्रक्रिया और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी। भारत में शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिसमें विद्यार्थियों की योग्यता का पैमाना परीक्षाओं में हासिल किए अंक ही होते हैं। 3 घंटे का प्रश्नपत्र कोई छात्र कैसे हल करता है और कितने अंक हासिल करता है, यही उसका भविष्य तय करते हैं। अंकों की दौड़ में बारहवीं कक्षा के परिणाम किसी भी छात्र के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ होते हैं। अगर परीक्षा की मूल्यांकन प्रणाली में ही गड़बड़ हो तो फिर यह छात्रों के भविष्य से सीधा खिलवाड़ है। एनसीईआरटी से जुड़े रहे कई शिक्षाविदों ने ओएसएम प्रणाली को बिना जांचे-परखे और जल्दबाजी में अपनाने का आरोप लगाया था लेकिन जब परिणाम आए तो ओएसएम प्रणाली की पोल खुल गई। जेनरेशन जैड के तीन छात्रों सार्थक सिद्धांत, वेदांत श्रीवास्तव और निसर्ग अधिकारी ने न सिर्फ कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं के लिए सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की पोल खोली बल्कि देशभर में नई बहस छेड़ दी। सार्थक सिद्धांत ने शिक्षा से जुड़ी संसदीय समिति के सामने पेश होकर प्रेजेंटेशन दी और माननीय सांसदों के सामने सीबीएसई की गड़बड़ियों को उजागर किया। छात्र वेदांत श्रीवास्तव का मामला तो काफी चिंताजनक है। वेदांत को जो उत्तर पुस्तिका मिली वह उसकी थी ही नहीं। दुखद बात यह रही कि जब वेदांत ने सवाल उठाए तो सोशल मीडिया पर उसे पाकिस्तानी करार दिया गया। उसे देशद्रोही और न जाने क्या-क्या कहा गया। भारतीय समाज के कुछ लोगों ने एक बच्चे को पाकिस्तानी और देशद्रोही करार देकर अपनी बीमार मानसिकता का ही परिचय दिया। यद्यपि सीबीएसई ने गलत उत्तर पुस्तिका अपलोड किए जाने पर माफी मांग ली, तब वेदांत को बुरा-भला कहने वाले भी शर्मसार हुए। सार्थक सिद्धांत ने ओएसएम अनुबंध से जुड़ी टैंडर प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया तो वहीं निसर्ग अधिकारी ने पोर्टल की गड़बड़ियों का भांडा फोड़ा। तीनों ही छात्र इस मामले में व्हिसल ब्लोअर साबित हुए। प्याज के छिलकों की तरह परत-दर-परत गड़बड़ियां सामने आने के बाद देशभर में सवाल उठने लगे। यह मामला महज एक तकनीकी समस्या से कहीं अधिक देश में परीक्षा प्रणाली की विफलताओं को उजागर करता है। सवाल उठा कि क्या सीबीएसई में कोई गिरोह हावी है जो बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर पैसा कमा रहा है। अब लाखों बच्चे री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीदों से कम अंक मिले हैं। सीबीएसई जैसी परीक्षा नियामक संस्था अभी तक खामियों को दूर करने के लिए कोई ठोस तंत्र विकसित नहीं कर पाई। हैरानी की बात यह है कि जिस कम्पनी को ओएसएम का अनुबंध दिया गया उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था। तेलंगाना में भी ऐसा ही प्रयोग किया गया था जहां एसएम प्रणाली सही नहीं कर पाई थी। भारत में नम्बरों की दौड़ लगी हुई है। नवम्बर कम आने पर छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभिभावक भी बच्चों को पैसे उगलने वाला एटीएम बनाना चाहते हैं और बच्चों पर बहुत मानसिक दबाव बनाते हैं। कई बार बच्चे भावनात्मक रूप से अपमानित और प्रताड़ित महसूस करते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। देशभर से अब बच्चों के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं और मामला ऊपरी अदालत में भी पहुंच चुका है लेकिन समाज को इस बात से सबक लेना होगा कि वे किसी और मासूम को ट्रोल न करें। सम्पन्न परिवारों के लोग तो पुनर्मूल्यांकन के लिए फीस देने की स्थिति में हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार क्या करेंगे। क्या सीबीएसई समूचा मूल्यांकन फिर से करवाने का साहस दिखाएगा या सालभर के प्रदर्शन के आधार पर सभी बच्चों को अंक दिए जाएंगे। धोखाधड़ी या गड़बड़ी का शिकार हुए छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा, यह बहुत गम्भीर सवाल है। सीबीएसई का माफीनामा या प्रशासनिक फेरबदल सुधार का विकल्प नहीं हो सकता। ओएसएम प्रणाली और स्कैनिंग प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच होनी ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीबीएसई की विश्वसनीयता कैसे कायम हो। अगर परीक्षा प्रणाली पर ही भरोसा नहीं तो फिर शिक्षा व्यवस्था में बचेगा क्या।

आई.एस.आई. का फर्जी सिखों के सहारे भारत विरोधी अभियान

पाकिस्तान द्वारा एक ओर सिख समुदाय के प्रति उदारवादी नीति अपनाते हुए सिख मसलों को गंभीरता से लेने की बात की जाती है, सिखों को उनके धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए समय-समय पर पाकिस्तान आने का न्यौता दिया जाता है, मगर वहीं दूसरी ओर पिछले लगभग 13 वर्षों से पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व को भारत के विपरीत जाकर अलग तारीखों में मनाया जा रहा है। इस बार शहीदी पर्व 18 जून को आ रहा है और समूचा संसार इसी दिन शहीदी पर्व को मनाएगा परन्तु पाकिस्तान में एक बार फिर से 16 जून को शहीदी पर्व मनाया जा रहा है, हालांकि इस बार यह देखने को मिला है कि भारत से जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के द्वारा 18 जून को ही शहीदी पर्व समागम किए जायेंगे, जिसकी जानकारी शिरोमणि कमेटी द्वारा सरकार को लिखे पत्र से प्राप्त हुई है। देखा जाए तो भारत की सिख जत्थेबंदियों की बड़ी जीत माना जा सकता है, जिसमें अहम रोल दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, महासचिव जगदीप सिंह काहलो और विशेष तौर पर परमजीत सिंह चंडोक ने अदा किया है। दूसरी ओर पिछले लंबे समय से पाकिस्तान भारत विरोधी दुष्प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाता रहा है। कभी आतंकवाद के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के जरिए और कभी धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वह न केवल चिंताजनक हैं बल्कि पूरे सिख कौम की धार्मिक पहचान और सम्मान पर सीधा हमला भी हैं। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. से जुड़े तत्व भारत, भारतीय सेना, भारतीय मीडिया और देश के सामाजिक ताने-बाने के खिलाफ जहर उगलने के लिए मुस्लिम और ईसाई युवाओं को सिखों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी सिख पहचान बनाकर भारत विरोधी वीडियो और सामग्री प्रसारित की जा रही है, ताकि दुनियाभर में यह भ्रम फैलाया जा सके कि सिख समुदाय भारत के खिलाफ खड़ा है। यह केवल फर्जी प्रचार नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र प्रतीत होता है। लाहौर के कासिफ अली आसिफ उर्फ कासिफ रंधावा द्वारा ''सरदार एम.के.पी.'' नाम से कथित रूप से संचालित फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट इसका एक उदाहरण बताया जा रहा है। आरोप है कि इस पहचान के माध्यम से दर्जनों भारत विरोधी वीडियो प्रसारित किए गए। इसी प्रकार सरदार मुहम्मद बिलावल नामक व्यक्ति द्वारा ''सिद्धू 39 वाला'' नाम से सिख स्वरूप धारण कर सोशल मीडिया गतिविधियां चलाने पर भी पाकिस्तानी सिखों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले को स्वयं पाकिस्तान के सिख समुदाय ने उठाया है। पाकिस्तान के सिख नेताओं और सामाजिक संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि गैर-सिख व्यक्तियों द्वारा पगड़ी और सिख पहचान का इस्तेमाल कर झूठी प्रसिद्धी हासिल करना तथा राजनीतिक या धार्मिक एजेंडा चलाना पूरी सिख बिरादरी के सम्मान के खिलाफ है। यह विरोध किसी दूसरे देश द्वारा नहीं, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले सिखों द्वारा उठाया गया है जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार रोका जा सकता था आज भी यह सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार टाला जा सकता था क्या पंजाब को उस भयावह दौर से बचाया जा सकता था और क्या कुछ राजनीतिक नेताओं की गलत रणनीतियों ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि अंततः सेना को दरबार साहिब परिसर में प्रवेश करना पड़ा पंजाब में तनाव 1978 के निरंकारी-सिख संघर्ष के बाद धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ा। इसी दौरान पंजाब केसरी के संस्थापक सम्पादक लाला जगत नारायण जी एक प्रमुख आवाज बनकर सामने आए। वह पंजाब केसरी और हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। लाला जगत नारायण जी खुलकर उग्रवाद, अलगाववाद और भिंडरावाले की नीतियों की आलोचना करते थे। उन्होंने अपने लेखों में पंजाब में बढ़ती कट्टरता और हिंसा के खिलाफ लगातार लिखा। यही कारण था कि वह उग्रवादी तत्वों के निशाने पर आ गए। 9 सितंबर, 1981 को उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या ने पूरे पंजाब में सनसनी फैला दी और हिंदू-सिख संबंधों में तनाव और बढ़ गया। जरनैल सिंह भिंडरांवाले की इस हत्या के मामले में संदेह के आधार पर गिरफ्तारी भी हुई, हालांकि बाद में तत्कालीन केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले और उन्हें रिहा कर दिया गया। भिंडरांवाले की लोकप्रियता उनकी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद और अधिक बढ़ गई। चार दशक बाद आज भी एक सवाल यही उठता है कि दरबार साहिब परिसर के अंदर हथियारों और गोला-बारूद का इतना बड़ा जखीरा कैसे पहुंचा। यह तथ्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 1983-84 तक परिसर के कुछ हिस्सों को किलेबंद कर दिया गया था और हथियारबंद लोग वहां मौजूद थे लेकिन यह कैसे हुआ, इस पर आज भी विवाद है। कोई सर्वमान्य न्यायिक निष्कर्ष नहीं है जो किसी एक संस्था या व्यक्ति को निर्णायक रूप से जिम्मेदार ठहराए। यदि शुरुआती चरण में ही स्थिति पर नियंत्रण किया जाता तो शायद इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। कृपाण आस्था का प्रतीक, विवाद का नहीं ब्रिटेन में हाल ही में कृपाण को लेकर छिड़ी बहस ने एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक सुरक्षा और सामुदायिक जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने ला दिया है।

सम्पादकीय...

बुढ़ापा पैंशन से 'प्राण वायु देवता पैंशन' तक - अनोखी पहल

हरियाणा की पहचान केवल कृषि, खेल और सैनिक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की अनेक जनहितकारी योजनाओं के कारण भी राज्य ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। जब भी वृद्धावस्था पैंशन की बात होती है तो लोगों को सबसे पहले चौधरी देवीलाल का नाम याद आता है। हरियाणा देश का पहला राज्य माना जाता है जिसने बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए बुढ़ापा पैंशन जैसी योजना को लागू किया। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग चौधरी देवीलाल को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। समय के साथ हरियाणा की विभिन्न सरकारों ने सामाजिक सुरक्षा की इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे नई सोच के साथ विस्तारित किया। इसी क्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 अक्तूबर 2023 को एक ऐसी अनोखी योजना शुरू की, जिसने न केवल देश बल्कि दुनिया का ध्यान भी आकर्षित किया। इस योजना का नाम है प्राण वायु देवता पैंशन योजना। आमतौर पर पैंशन मनुष्यों को दी जाती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृक्षों को भी सम्मान देने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत ऐसे वृक्षों के संरक्षण और देखभाल के लिए उनके मालिकों को प्रतिवर्ष 2750 रुपए की पैंशन प्रदान की जाती है। योजना की बढ़ती लोकप्रियता और जनभागीदारी को देखते हुए सरकार ने अब इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। योजना शुरू होने के समय लगभग 3810 वृक्ष इसके अंतर्गत पंजीकृत थे, जिन्हें वार्षिक पैंशन का लाभ दिया जा रहा था। आज इन वृक्षों की संख्या बढ़कर लगभग 5000 तक पहुंच चुकी है। यह केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और वृक्षों को केवल लकड़ी या भूमि उपयोग के साधन के रूप में नहीं बल्कि जीवनदाता के रूप में देखने लगे हैं।वास्तव में वृक्ष मानव जीवन के सबसे बड़े संरक्षक हैं। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, भूजल संरक्षण में मदद करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं और जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण और जनसंख्या दबाव के कारण दुनिया भर में जंगलों का क्षेत्र लगातार घट रहा है। इसका सीधा प्रभाव जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे समय में यदि किसी राज्य की सरकार वृक्षों को सम्मान देने और उनके संरक्षण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती है तो यह निश्चित रूप से एक दूरदर्शी और अनुकरणीय पहल कही जाएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसी सोच को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरूआत की। यह अभियान केवल पौधारोपण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि भावनाओं से जुड़ा एक जनआंदोलन बन गया। इस अभियान के अंतर्गत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 80 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया।

अभी चंडीगढ़ दूर है

पश्चिम बंगाल के बाद बम-बम भारतीय जनता पार्टी यह प्रभाव दे रही है कि अगला किला जो वह फतह करने जा रहे हैं, वह पंजाब होगा। बंगाल की जीत के बाद चंडीगढ़ में पार्टी दफ्तर के बाहर यह नारा लगाया गया, 'बंगाल की जीत हमारी है, अब पंजाब की बारी है-'। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना था कि अगर पार्टी बंगाल में तीन सीट से दो-तिहाई तक छलांग लगा सकती है तो पंजाब में वह यह क्यों दोहरा नहीं सकती तब से सुनील जाखड़ खुद बदले जा चुके हैं और उनकी जगह मल्टी-मिलिनियर केवल सिंह ढिल्लों जो सुनील जाखड़ की ही तरह कांग्रेस में रहे हैं, को नया अध्यक्ष बना दिया गया है। जहां तक सुनील जाखड़ के सवाल का सम्बन्ध है, इसका सीधा जवाब है कि पंजाब बंगाल नहीं है, और भगवंत मान की आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस नहीं है और न चंडीगढ़ कोलकाता है। स्थानीय निकाय चुनावों में आप को भारी जीत मिली है। दूसरे नम्बर पर कांग्रेस, फिर आजाद, फिर शिरोमणि अकाली दल और अंत में भाजपा रहे हैं। पंजाब और बंगाल दोनों सीमावर्ती प्रांत हैं, पर दोनों का इतिहास, संस्कृति, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक हालत अलग है। यहां न तो हिन्दू-मुसलमान का कोई मसला है और न ही घुसपैठियों की कोई समस्या है। न ही नफ़रत फैलाने वाले नेता हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत हिंसक हो चुकी है जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तथा सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमले से भी पता चलता है। पंजाब में वह हथकंडे नहीं अपनाए जा सकते जो कुछ प्रदेशों में अपनाए गए हैं। मिलिटैंसी के समय भी यहां साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। पंजाब के मुद्दे और हैं, पर हम सौभाग्यशाली हैं, उन मुद्दों में नफ़रत शामिल नहीं है। सरबत दा भला की भावना साम्प्रदायिक राजनीति से मेल नहीं खाती। स्थानीय निकाय के चुनाव बता गए हैं कि यहां अभी शासन विरोधी भावना नहीं है। भाजपा का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा है। 2021 में वह 49 वार्ड जीतने में सफल रहे थे जो अब बढ़कर 172 हो गए हैं। अबोहर नगर निगम में इन्हें बहुमत मिला है और पठानकोट में वह सबसे बड़ी पार्टी है, पर बाकी निगमों में वह बहुत पीछे है और नगर पंचायतों में भाजपा का खाता भी नहीं खुला। भाजपा के नेता बहुत जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी एससी वोट को प्रभावित करने के लिए प्रभावशाली डेरा बल्लां आ चुके हैं। ब्यास डेरे से भी सम्पर्क किया जा रहा है। पंजाब में एससी वोट 32% है जो 117 में से 23 सीटें सीधा प्रभावित करता है। दोआबा में यह आबादी 45% है। इसी वोटर ने पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। भाजपा का नेतृत्व इसी वोटर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन चल उल्टे रास्ते पर है। केवल सिंह ढिल्लों जिनके बारे बताया जाता है कि उनके न केवल देश में कई घर है बल्कि दुबई और स्पेन में भी है, को पार्टी अध्यक्ष बना कर भाजपा दलित वोट को कैसे आकर्षित करेगी न जाने भाजपा नेतृत्व में उच्च वर्ग के जाट नेताओं (अमरेन्द्र सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू, केवल सिंह ढिल्लों, तरनजीत सिंह संधू) का इतना आकर्षण क्यों है क्या किसान आंदोलन से पैदा हुई नाराजगी को कम करने का प्रयास हो रहा है भाजपा का अपना समर्थन और अपना काडर गैर-सिख है। प्रदेश भाजपा के पास समर्पित नेताओं की कमी नहीं है। यह लोग पार्टी की दिशा को देखकर भौंचक्के हैं। पार्टी का नेतृत्व अपने लोगों को आगे करने की जगह राजनीतिक इम्पोर्ट पर भरोसा कर रहा है। कोशिश हो रही है कि देहात में पार्टी के पैर जम जाए, पर यह परिणाम तो उल्टा संदेश देते हैं। सिख उस पार्टी का समर्थन नहीं देंगे हिन्दुत्व जिसका मूल सिद्धांत है। इस इम्पोर्ट से पार्टी के अपने लोगों में बेचैनी है। उल्लेखनीय है कि न्यू अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के बरनाला में भाजपा केवल 7 वार्ड ही जीत सकी। शहरी निगमों में भाजपा का यह हाल है कि बठिंडा में 1, बटाला में 2, कपूरथला में 3, मोगा में 3, मोहाली में 3, सीटें ही मिली हैं। भाजपा का परम्परागत वोट हिन्दू है। समझा जा रहा है कि नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता के कारण यह कहीं नहीं जाएगा, पर यह परिणाम तो और ही कुछ बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन नहीं मिला और शहरी क्षेत्र में लोग नाखुश हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट से स्थिति और खराब हो रही है। अखिल भारतीय परीक्षा का घोटाला छवि प्रभावित कर रहा है। पंजाब की स्थिति अलग है, वह असम या बंगाल नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि अच्छे समय में जब यहां अकाली-भाजपा सरकार थी अरुण जेतली जैसा बड़ा नेता अमृतसर से हार गया था। यही हालत हरदीप सिंह पुरी और तरनजीत सिंह संधू की बनी थी। जब तक लोगों, विशेष तौर पर ग्रामीण, का विश्वास हासिल नहीं होता भाजपा की दाल गलने वाली नहीं, उन्हें तो अपने शहरी वोटर की चिन्ता करनी चाहिए जो अपनी अनदेखी से नाराज हैं। कहीं यह हालत न बने कि माया मिली न राम ! भाजपा ने 100 वार्डों में जमानत गवां दी है। अकाली दल के साथ गठबंधन का विकल्प है, पर तब अतीत का बोझ भी साझा करना पड़ेगा। चाहे यह प्रभाव दिया जा रहा है कि मुकाबला आप और भाजपा में है, यह हकीकत नहीं है। असली मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच है, शर्त यह है कि कांग्रेस अपना अव्यवस्थित घर सही करने में सफल हो जाए, जिसके कोई संकेत अभी नज़र नहीं आ रहे। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 4 नगर निगम थे जो अब गिरकर 1 रह गया है, पर बटाला, पठानकोट, मोहाली में प्रदर्शन बुरा नहीं रहा। कांग्रेस की बड़ी समस्या है कि उनके पास नेताओं की भरमार है। प्रताप सिंह बाजवा, अमरेन्द्र सिंह वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिन्दर सिंह रंधावा सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पार्टी इन सिख नेताओं में उलझी हुई है जबकि कांग्रेस का असली आधार हिन्दू और एससी वोटर है। जब से पंजाब में आप सत्तारूढ़ हुई है कांग्रेस छह उपचुनाव हार चुकी है। यह कैसे सोच लिया कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में ऐसा विभाजित नेतृत्व आप को चुनौती दे सकेगा यह लोग आप का मुकाबला करने की जगह एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि हाईकमान निंद्रा में है या सारा ध्यान दक्षिण पर है। हिमाचल में हुए चार निगम चुनाव में भाजपा तीन जीत गई है। यह कैसे हो गया जबकि समझा यह जाता है कि ऐसे चुनावों में सत्ता पक्ष का हाथ ऊपर रहता है। लगता है कि हिमाचल भी उसी तरह हाईकमान की उपेक्षा का शिकार है जैसे पंजाब है, अगर हालात नहीं सुधरे तो हिमाचल प्रदेश जो उत्तर भारत में कांग्रेस का एकमात्र प्रदेश है, भी अगले साल हाथ से फिसल सकता है। पंजाब के बारे भी कांग्रेस के नेतृत्व को किसी गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए। अगर चंडीगढ़ भाजपा के लिए दूर है तो अभी कांग्रेस की पहुंच से भी बाहर नज़र आता है। कारण है कि मुकाबला भगवंत मान की आप से है। मैंने इसे 'भगवंत मान की आप' इसलिए कहा है क्योंकि मान अब अरविंद केजरीवाल की परछाई से बाहर आ चुके हैं और आगे आकर नेतृत्व दे रहे हैं। पोस्टर और विज्ञापन पर भी अब अकेले भगवंत मान की तस्वीर होती है। अंतर भी साफ़ है। केजरीवाल एक पराजित मुख्यमंत्री है जबकि भगवंत मान को अभी तक कोई धक्का नहीं पहुंचा। पंजाब से छह राज्यसभा सांसदों का दलबदल जरूर बुरा था, पर वह दोनों के बराबर हिस्से आया है, क्योंकि चुनाव दिल्ली से हुए थे। संतुलन कैसे मान की तरफ़ झुक गया यह इससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि यह परिणाम -मान सरकार के कामों को शाबाशी है-। भगवंत मान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह वे नहीं जो पहले मुख्यमंत्री थे ! न वह एनसी ठाठ न दूसरी कमज़ोरियां। शुरू में उनका कम आंकलन किया गया। समझा गया कि वह एक कामेडियन है क्या सरकार चलाएंगे इसीलिए राघव चड्ढा को उनके सिर पर बैठा दिया गया लेकिन समय के साथ भगवंत मान समर्थन और आत्मविश्वास हासिल करते गए। जिस प्रकार वह आम जनता के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं वह क्षमता बहुत कम नेताओं के पास है। वह मज़ाक-मज़ाक में वज़नदार बात कह जाते हैं। भाजपा को 'ईडी पार्टी' कह चुके हैं। छह राज्यसभा सांसदों के दलबदल पर कहना है कि पंजाब में भाजपा के 2 विधायक हैं, पर राज्यसभा में 6 सांसद हैं। यह जायज है- लोग उनकी बात समझते हैं, इसलिए जो पार्टियां आप को हटाना चाहती हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि मुकाबला भगवंत मान से है जिनके खिलाफ़ इस वक्त तक कुछ नहीं है। कोई सरकार विरोधी लहर नज़र नहीं आती। हां, पंजाब के सामने कई चुनौतियां हैं कर्ज़ा 4 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। नशा-तस्करी हो रही है, गैंगस्टरवाद फैल रहा है, कई जगह बम विस्फोट हो चुके हैं। क्राइम बढ़ा है, पर नशा और गैंगस्टर वाद की समस्या उन्हें विरासत में मिली है। पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस की सरकारें कर्ज़ा और व्यापक ड्रग-गैंगस्टर संस्कृति छोड़ गई है। पर हां, इन्हें सम्भालना वर्तमान सरकार की ज़िम्मेवारी है। वह यह काम

अग्निकांडों से सीख- यह केवल एक व्यक्ति या संस्था की नहीं बल्कि पूरे तंत्र की विफ़लता

वैश्विक स्तर पर फिर एक बार हड़कंप मच गया जब दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में 3 जून 2026 को हुए भीषण अग्निकांड में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और घायल होने की खबर ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जब किसी होटल,अस्पताल, मॉल, स्कूल, औद्योगिक इकाई या व्यावसायिक भवन में आग लगती है तो आखिर ऐसी त्रासदी केवल आग के कारण होती है या उसके पीछे वर्षों से जमा होती आ रही प्रशासनिक, तकनीकी और संस्थागत विफलताओं की लंबी श्रृंखला भी जिम्मेदार होती है। दुनियाँ के किसी भी देश में आग लगना एक दुर्घटना हो सकती है,लेकिन आग के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होना अक्सर एक प्रणालीगत विफलता माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश बड़े अग्निकांडों में मौतें केवल आग से नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी, निकासी व्यवस्था की कमी, आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी,निरीक्षण तंत्र की कमजोरी और भ्रष्टाचार के कारण होती हैं।इसलिए किसी भी अग्निकांड की जांच केवल यह पता लगाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि आग कैसे लगी, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी गई। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि, 3 जून 2026 की सुबह भारत की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल और उससे जुड़े रेस्तरां में लगी भीषण आग ने केवल 21 से अधिक लोगों की जान नहीं ली,बल्कि देश की शहरी सुरक्षा व्यवस्था,नियामक तंत्र, प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा संस्कृति पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया। मीडिया में आए प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भवन को केवल 6 कमरों की अनुमति थी,जबकि वहां लगभग 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह सामने आया कि भवन के पास वैध फायर एनओसी नहीं थी तथा अंदर आने- जाने के लिए प्रभावी आपातकालीन निकास व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। बेसमेंट में लोगों के फंस जाने की खबरों ने स्थिति को और भयावह बना दिया।इस त्रासदी में 21 लोगों की मृत्यु हुई, 40 से अधिक लोगों को बचाया गया तथा अनेक गंभीर रूप से घायल अस्पतालों में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मृतकों में मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों के कई विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो भारत में चिकित्सा उपचार या अन्य कारणों से आए थे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग धुएं और लपटों से बचने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से कूदने को मजबूर हो गए, जबकि स्थानीय नागरिक सीढ़ियां और गद्दे बिछाकर उनकी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। यह घटना किसी भूकंप, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं थी, बल्कि प्रथम दृष्टया मानवीय लापरवाही,नियमों कीअवहेलना भ्रष्टाचार, कमजोर निगरानी और जवाबदेही की कमी का परिणाम प्रतीत होती है। यही कारण है कि यह दुर्घटना केवल एक होटल अग्निकांड नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय शहरी प्रशासन की विफलताओं का प्रतीक बन गई है। साथियों बात अगर हम ऐसी घटनाओं के भारतीय इतिहास की करें तो, भारत का इतिहास ऐसी दर्दनाक घटनाओं से भरा पड़ा है। वर्ष 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा फायर में 59 लोगों की मृत्यु हुई थी। जांच में सामने आया कि आपातकालीन निकास मार्ग अवरुद्ध थे, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था तथा प्रबंधन और प्रशासन दोनों स्तरों पर गंभीर लापरवाही हुई थी। वर्ष 2004 में कुम्भकोणम स्कूल फायर में 94 स्कूली बच्चों की मृत्यु हुई।विद्यालय में अग्नि सुरक्षा प्रबंधअत्यंत कमजोर थे और ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया गया था। वर्ष 2019 में अनाज मंडी फायर में 43 लोगों की मृत्यु हुई, जहां फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी और निकास व्यवस्था अपर्याप्त थी। उसी वर्ष दिल्ली के मुंडका फायर ट्रेजेडी जैसे मामलों में भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल के अमरी हॉस्पिटल फायर में 90 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, जहां धुएं और आपातकालीन प्रबंधन की विफलता प्रमुख कारण बनी। इन सभी घटनाओं में एक समान पैटर्न दिखाई देता है,नियमों का उल्लंघन, कमजोर निरीक्षण, भ्रष्टाचार, अपर्याप्त फायर ऑडिट और एजेंसियों के बीच सटीकता से समन्वय की कमी। साथियों, किसी भी बड़े शहर में अग्निशमन सेवा या फायर ब्रिगेड अंतिम रक्षा पंक्ति होती है। जब आग लग जाती है तब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या फायर विभाग ने भवन का समय- समय पर निरीक्षण किया था, क्या भवन के पास वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र था,क्या अग्निशमन उपकरण कार्यरत थे, क्या स्प्रिंकलर सिस्टम और स्मोक डिटेक्टर सक्रिय थे और क्या भवन मालिकों ने नियमों का पालन किया था। अनेक मामलों में देखा गया है कि फायर विभाग निरीक्षण तो करता है लेकिन बाद में नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई देशों में जांच रिपोर्टों ने यह दिखाया है कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र मिलने के बाद वर्षों तक दोबारा प्रभावी निरीक्षण नहीं होता। परिणामस्वरूप भवनों में अतिरिक्त कमरे, अवैध निर्माण, बंद आपातकालीन निकास और क्षमता से अधिक लोगों को रखने जैसी खतरनाक स्थितियाँ विकसित हो जाती हैं। यदि किसी भवन को छह कमरों की अनुमति मिली हो और बाद में उसमें कई गुना अधिक कमरे बना दिए जाएं तो यह केवल भवन मालिक की गलती नहीं बल्कि निगरानी तंत्र कोसटीकता से विफलता भी मानी जाएगी। साथियों पुलिस की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।सामान्यतः पुलिस को आपदा के समय कानून- व्यवस्था बनाए रखने,बचाव कार्यों को सुगम बनाने और अपराध संबंधी जांच करने का दायित्व दिया जाता है। लेकिन कई बार पुलिस का स्थानीय स्तर पर भवनों, होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बारे में पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं होता। कुछ मामलों में अवैध गतिविधियों या नियमों के उल्लंघन की जानकारी होने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती। आपदा के बाद पुलिस अक्सर जांच शुरू करती है,जबकि वास्तविक आवश्यकता जोखिमों की पूर्व पहचान और निवारक कार्रवाई की होती है।विकसित देशों में पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच डेटा साझा करने की व्यवस्था होती है जिससे जोखिम वाले भवनों की पहचान पहले से की जा सके। भारत सहित अनेक विकासशील देशों में यह समन्वय अभी भी सीमित दिखाई देता है। साथियों,आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की जिम्मेदारी केवल आपदा के बाद राहत देना नहीं बल्कि जोखिम को कम करना भी है।यदि किसी महानगर में हजारों होटल, हॉस्टल अस्पताल और व्यावसायिक इमारतें हैं तो यह सुनिश्चित करना आपदा प्रबंधन संस्थाओं का भी दायित्व है कि आपातकालीन निकासी योजना,मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित हों।

अक्सर पाया जाता है कि मॉक ड्रिल केवल कागजों में पूरी हो जाती है या सीमित स्तर पर आयोजित होती है। जब वास्तविक आपदा आती है तब कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और भवन प्रबंधक नहीं जानते कि लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। इससे भगदड़, घबराहट और मृत्यु की संख्या बढ़ जाती है। एम्बुलेंस सेवाओं और चिकित्सा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की कमियाँ भी अनेक बार सामने आती हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी बड़े शहर में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया का समय न्यूनतम होना चाहिए। लेकिन ट्रैफिक जाम, अपर्याप्त एम्बुलेंस, समन्वय की कमी और अस्पतालों में तैयारी के अभाव के कारण घायल लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। अग्निकांडों में धुएं से दम घुटना एक प्रमुख कारण होता है और ऐसे मामलों में शुरुआती कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि चिकित्सा सहायता में देरी होती है तो बचाई जा सकने वाली जानें भी चली जाती हैं। साथियों, स्थानीय निकायों और नगर निगमों की जवाबदेही शायद सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि भवन निर्माण की अनुमति,उपयोग परिवर्तन, व्यापार लाइसेंस और भवन सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। दुनियाँ भर में हुई अनेक त्रासदियों की जांच में पाया गया कि भवन निर्माण नियमों का पालन नहीं किया गया था। कहीं अवैध मंजिलें बनाई गई थीं, कहीं निकास मार्ग बंद थे, कहीं विद्युत तारों का रखरखाव खराब था और कहीं अग्नि सुरक्षाउपकरण केवल दिखावे के लिए लगाए गए थे। यदि किसी नगर निकाय के रिकॉर्ड में भवन की एक स्थिति दर्ज हो और वास्तविकता में वह पूरी तरह अलग हो, तो यह निरीक्षण और प्रवर्तन तंत्र की गंभीर विफलता का संकेत है। साथियों, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे संवेदनशील लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अनेक देशों में हुई आपदाओं की जांच रिपोर्टों ने यह संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को कभी-कभी रिश्वत, राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक उदासीनता के कारण संरक्षण मिल जाता है। जब सुरक्षा प्रमाणपत्र पैसे या प्रभाव के आधार पर जारी होने लगें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने करण ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पॉवरहाउस एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/80882)

आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा-2025 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

कुशीनगर।

उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की आगामी लिखित परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जनपद के पांच परीक्षा केंद्रों पर विभिन्न तिथियों में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी पूर्व में भी

परीक्षा को नकलविहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दिए गए कड़े निर्देश

परीक्षाओं का सफल संचालन कर चुके हैं, लेकिन छोटी-सी असावधानी भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि ड्यूटी का सटीक आवंटन, प्रश्नपत्र बॉक्स को निर्धारित समय पर सुरक्षित तरीके से खोलना, प्रश्नपत्रों का

वितरण एवं संकलन तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही पेपर लीक जैसी किसी भी संभावना को रोकने के लिए सभी बिंदुओं पर पैनी निगरानी रखी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा चश्मे अथवा अन्य उपकरणों के माध्यम से किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने सभी कार्मिकों को अधिक सजग और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी पांचों परीक्षा केंद्रों पर एम्बुलेंस और चिकित्सकीय टीम की तैनाती भी अनिवार्य रूप से करने को कहा। उन्होंने बताया कि एक पाली में 2112 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि कुल लगभग 12 हजार अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होंगे। तैयारियों को परखने के लिए 6 जून 2026 को रिहर्सल भी कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कुशेश्वर कुमार ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में नकल के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं, इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अत्यंत सतर्क एवं संवेदनशील रहना होगा। उन्होंने कक्ष निरीक्षकों की तैनाती, उनकी जांच तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा को पूर्णतः नकलविहीन, शांतिपूर्ण एवं शासन की गाइडलाइन के अनुरूप सम्पन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा सभी व्यवस्थाओं की बारीकियों से अवगत कराया।

कप्तानगंज रेलवे ढाला पर बनेगा अंडरपास, सर्विस रोड व ड्रेन 12 करोड़ स्वीकृत

कप्तानगंज(कुशीनगर)।

कस्बे के सुभाष चौक के बहुप्रतीक्षित कप्तानगंज रेलवे ढाला पर अंडरपास, सर्विस रोड एवं ड्रेन निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। क्षेत्रीय सांसद विजय दुबे की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उक्त परियोजनाओं के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस घोषणा के बाद नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताते चले कि कप्तानगंज रेलवे ढाला पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी जिसको लेकर फ्लाइओवर का निर्माण हुआ और आठ माह पूर्व उद्घाटन सांसद ने किया था मगर रेलवे ढाला बार-बार बंद होने व सर्विस लेन सड़क व नाला खराब होने के कारण कप्तानगंज नगर वासियों राहगीरों, व्यापारियों तथा स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या और गंभीर हो जाती है। लंबे समय से स्थानीय लोग अंडरपास, सर्विस रोड और बेहतर जलनिकासी व्यवस्था की मांग कर रहे थे। आए दिन धरना

*गोलू मिश्रा के प्रदर्शन पर सांसद ने लिया संज्ञान

प्रदर्शन भी हो रहा था जिसको लेकर दो दिन पूर्व समाजसेवी गोलू मिश्रा ने आम जनता के साथ सुभाष चौक चौराहे पर प्रदर्शन भी किया था जिसको गंभीरता से लेते हुए सांसद विजय दुबे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की थी। सांसद की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने 12 करोड़ रुपये की मंजूरी देते हुए निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया। सांसद विजय दुबे ने कहा कि यह परियोजना पूरी होने से नगर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी और लोगों को जाम एवं जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। परियोजना की स्वीकृति की खबर मिलते ही नगर के लोगों, व्यापारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड पडी उन्होंने सांसद विजय दुबे को धन्यवाद दिया।

जनता दर्शन में बरती लापरवाही तो बीडीओ पथरदेवा को प्रतिकूल प्रविष्टि, दो महिलाओं के तुरंत बने राशन कार्ड

देवरिया।

शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने विधिक और प्रशासनिक रुख कड़ा कर लिया है। कलेक्ट्रेट में गुरुवार को आयोजित जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने एक फरियादी के प्रकरण में अनावश्यक विलंब और शिथिलता पाए जाने पर खंड विकास अधिकारी पथरदेवा को तत्काल प्रभाव से प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश जारी किए है। जिलाधिकारी के इस कड़े कदम से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। विधिक प्रकरण के अनुसार, पथरदेवा विकासखंड के ग्राम धर्मचौरा निवासी प्रमोद साहनी ने जनता दर्शन में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2022 में उन्हें मत्स्य पालन के लिए तालाब का विधिक पट्टा आवंटित हुआ था, परंतु धरातल पर कार्य शुरू नहीं हो सका। फरियादी ने बताया कि इस समस्या को लेकर वह पूर्व में भी कई बार जिला मुख्यालय पर गुहार लगा चुका है।

मामले की समीक्षा में पाया गया कि जिलाधिकारी स्तर से बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद खंड विकास अधिकारी पथरदेवा द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली गई और शासकीय फाइल को अकारण लंबित रखा गया। इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जनशिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च विधिक प्राथमिकताओं में है, जिसमें किसी भी स्तर पर हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी। इसके विपरीत, जनता दर्शन में त्वरित न्याय और संवेदनशीलता का एक सकारात्मक उदाहरण भी सामने आया। राशन कार्ड न बनने से परेशान दो अत्यंत जरूरतमंद महिलाएं

तालाब पट्टे के निस्तारण में अनावश्यक विलंब पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जताई कड़ी नाराजगी

जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुईं। बैतालपुर विकासखंड की निवासी विमला देवी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने और राशन कार्ड न होने के कारण उन्हें सरकारी खाद्यान्न योजना का विधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं, गरुलपार की निवासी सविता वर्मा ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उनके पति गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और आजीविका का कोई सुदृढ़ साधन न होने से परिवार संकट में है। मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही जिला पूर्ति अधिकारी को पात्रता की जांच कर तत्काल राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक तत्परता से कुछ ही घंटों में दोनों पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड बनकर तैयार हो गए, जिस पर दोनों महिलाओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन का विधिक आभार प्रकट किया।

अपहृत युवती की बरामदगी के बाद वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

भटनी पुलिस ने चांदपार अंडरपास से दबोचा

भटनी देवरिया। पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भटनी पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 127/2026, धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त अर्जुन (21 वर्ष), निवासी नेबु कबीरपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया को गुरुवार को चांदपार अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि इसी मामले में संबंधित पीड़िता को थाना भटनी पुलिस द्वारा पूर्व में 30 मई 2026 को सकुशल बरामद कर लिया गया था। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी थानाध्यक्ष अजय कुमार तिवारी, कांस्टेबल जयदीप दूबे तथा रिक्रूट कांस्टेबल शिवम सिंह शामिल रहे।

गौतमबुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर नियमित उड़ानों के विस्तार की मांग, नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग को नई गति देने पर जोर

गोरखपुर/भैरहवा । नेपाल और भारत के बीच आर्थिक, व्यापारिक तथा निवेश सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाकर साझा समृद्धि की मजबूत नींव तैयार करने की आवश्यकता पर दोनों देशों के सरकारी एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने जोर दिया है। साथ ही गौतमबुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल के पूर्ण संचालन, सीमावर्ती क्षेत्रों के औद्योगिक विकास तथा लुम्बिनी के अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रवर्द्धन में भारतीय निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया। भारत के गोरखपुर में आयोजित 'भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग मंच-2026' में वक्ताओं ने कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, बैंकिंग, पूर्वाधार, औद्योगिक निवेश तथा सीमापार व्यापार को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नेपाली निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने गौतमबुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए भारतीय विमान सेवा कंपनियों और निजी क्षेत्र से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। उनका कहना था कि विमानस्थल का पूर्ण एवं प्रभावी संचालन लुम्बिनी क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई गति

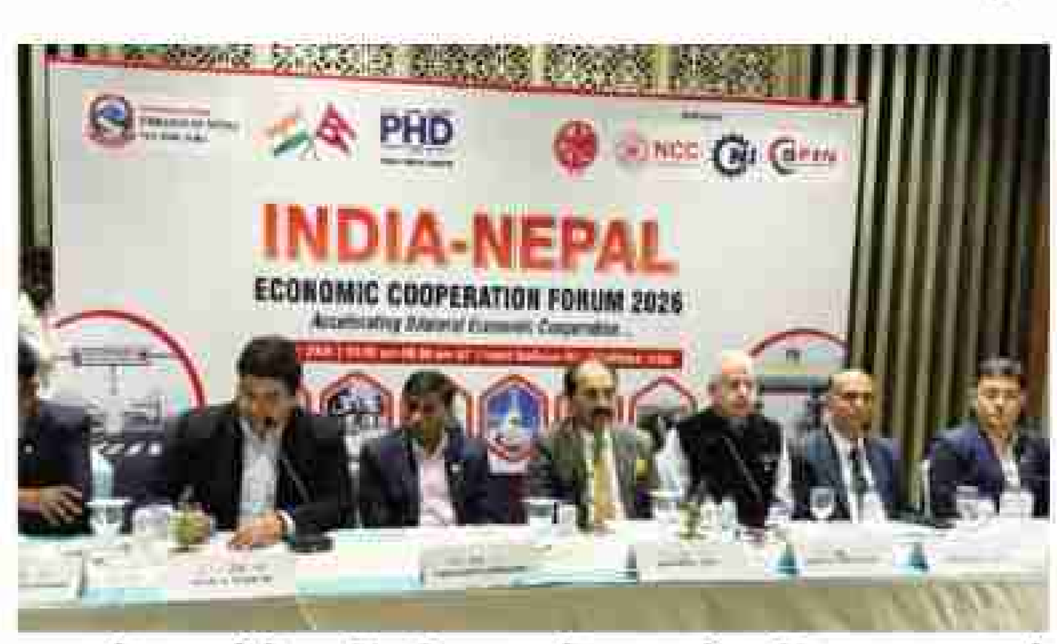

प्रदान करेगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। चर्चा के दौरान भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में भारतीय उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत और व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया गया। वक्ताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों की औद्योगिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग करते हुए संयुक्त निवेश और उत्पादन विस्तार की दिशा में ठोस पहल करने का सुझाव दिया।

लुम्बिनी को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय पर्यटन व्यवसायियों और निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका पर भी जोर दिया गया। वक्ताओं ने सुझाव दिया कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी को भारतीय बौद्ध श्रद्धालुओं तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए संयुक्त प्रचार अभियान चलाए जाने चाहिए।

भारत स्थित नेपाली दूतावास के सहसचिव तारानाथ अधिकारी ने कहा कि नेपाल और भारत के आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए व्यापार, पर्यटन, निवेश और पूर्वाधार विकास के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच बढ़ती साझेदारी आर्थिक समृद्धि की मजबूत आधारशिला बन सकती है। नेपाल दूतावास के आर्थिक परामर्शदाता रवीन्द्रजंग थापा ने नेपाल में निवेश, उद्योग, पर्यटन और व्यापार की अपार संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा ने व्यापार सहजीकरण, निवेश-अनुकूल वातावरण के निर्माण और सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि नेपाल-भारत आर्थिक संबंधों को व्यावहारिक और परिणाममुखी बनाने में निजी क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग मंच के सचिव, उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम अध्यक्ष कमलेश जैन ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों, आर्थिक सहयोग की संभावनाओं और निजी क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए साझेदारी को और अधिक परिणाममुखी बनाने का आह्वान किया। भारतीय उद्योगपति अनुकूल भटनागर ने नेपाल और भारत के ऐतिहासिक संबंधों को आर्थिक विकास से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि व्यापार, उद्योग, निवेश और वित्तीय सहयोग के विस्तार से दोनों देश पारस्परिक लाभ प्राप्त कर सकते है।

मालवीय नगर अग्निकांड में घायलों का का हाल जानने साकेत मैक्स अस्पताल पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को साकेत स्थित मैक्स अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मालवीय नगर आग त्रासदी में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके इलाज की समीक्षा की। यह दौरा आग की उस घटना के बाद हुआ जिसने राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख दिया था। इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इस बीच, पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पीड़ितों और उनके परिवारों से बातचीत की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पीड़ितों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपाध्याय ने कहा, मुख्यमंत्री आज (मैक्स अस्पताल, साकेत) यहाँ आईं। यहाँ कुल 17 लोग भर्ती हैं। इनमें से सात लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे (पीड़ितों से) बात की है, और हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें अच्छा इलाज मिले। कल की तुलना में पीड़ितों की सेहत में काफी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री आगे के फैसले लेंगी। हमारी प्राथमिकता पीड़ितों की सेहत है। प्रत्यक्षदर्शी रियाजुद्दीन मंसूरी ने बचाव अभियान के दौरान अपने प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने लोगों को आग की लपटों से बचने के लिए इमारत से कूदते देखा, तो उन्होंने सड़क पर गद्दे बिछाकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की। उन्होंने एएनआई को बताया, जब मैंने लोगों को इमारत से कूदते देखा, तो मैंने अपनी दुकान से गद्दे लाकर सड़क पर बिछा दिए, जिससे आठ लोगों की जान बच गई। हमने सबों को बचाने के लिए जितना हो सका उपलब्ध कराई। फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच गई थी। हमने 20 से ज्यादा लोगों को बचाया। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी, मोहम्मद वसीम खान ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने होटल के मालिक से बात की और उन्हें सूचित किया कि वह घटना स्थल पर पहुँच गए हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मालिक ने लोगों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया; उसने कहा कि उसे घटना के बारे में पता था, लेकिन आग की तीव्रता का अंदाज़ा नहीं था। मैं सुबह 8.30 बजे घटनास्थल पर पहुँचा। मैंने देखा कि हालात बेहद गंभीर थे... मैंने सुबह 8.52 बजे मालिक को फ़ोन किया। मैंने उन्हें 26 सेकंड बात की। मैंने उन्हें बताया कि लोगों के बचने की उम्मीद बहुत कम है... हाँ, मालिक यहाँ आए थे। मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि वे कब आए या कितनी देर रुके, क्योंकि मैं लोगों की जान बचाने में व्यस्त था... उन्होंने किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की... उन्हें पक्का पता था कि उनके होटल में आग लगी है, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि आग कितनी बड़ी थी, उन्होंने कहा।

राज्यसभा चुनाव- कांग्रेस ने सात उम्मीदवारों के नामों का किया एलान, कर्नाटक से मैदान में खरगे और पवन खेड़ा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद सात उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से जारी सूची के अनुसार, कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया गया है। राजस्थान से नीरज डांगी को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है, जबकि तमिलनाडु से अर्थशास्त्री और पार्टी के रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है।

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने सात उम्मीदवारों का एलान कर दिया है, जिसमें पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग और राहुल गांधी की कोर टीम पर सबसे बड़ा भरोसा जताया है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा की लंबे समय बाद तपस्या पूरी हुई है और उन्हें कर्नाटक से टिकट मिला है।

कर्नाटक में मजबूत स्थिति

कर्नाटक की चार खाली सीटों में से कांग्रेस अपने संख्या बल के आधार पर तीन सीटें आसानी से जीत सकती है। इसी वजह से पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को यहां से सुरक्षित सीट पर उतारा है। सूची में मीनाक्षी नटराजन (मध्य प्रदेश) और प्रवीण चक्रवर्ती (तमिलनाडु) के नामों से साफ है कि टिकट बंटवारे में राहुल गांधी की पसंद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

पवन खेड़ा की तपस्या पूरी

लंबे समय से पार्टी का मीडिया चेहरा रहे पवन खेड़ा को आखिरकार संसद भेजने का फैसला किया गया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार पर लगाए आरोपों के बाद वे कानूनी विवादों में भी घिरे रहे, लेकिन पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। शुक्रवार को बंगलूरू में जब मल्लिकार्जुन खरगे अपना पर्चा दाखिल करेंगे, तब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद वहां मौजूद रहेंगे, जो इस नामांकन को एक बड़ा राजनीतिक संदेश बनाएगा।

मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने किया सरेंडर

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सिमकनों में आयोजित पार्टी की जनसभा में खराब मौसम के कारण राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से तो नहीं पहुंच सके, उन्होंने दिल्ली से ही फोन के माध्यम से जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने देश की विदेश नीति, कृषि और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। बृहस्पतिवार को आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश की विदेश नीति को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका भारत को दबाव में ले रहा है और वह तय कर रहा है कि भारत को किस देश से तेल खरीदना चाहिए और किससे नहीं। विदेश नीति के साथ-साथ कांग्रेस नेता ने सरकार की घरेलू नीतियों पर भी तीखा प्रहार किया।

जम्मू के रियासी में बादल फटा, कई घरों को नुकसान

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के बटोही इलाके में गुरुवार को बादल फट गया। इसके बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी और मलबा रिहायशी क्षेत्र में घुस गया, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पहाड़ी ढलानों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। दूसरी ओर, दक्षिण-पश्चिम मानसून गुरुवार को केरल पहुंच गया। अगले 2-3 दिनों में इसके गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचने की संभावना है। मानसून पूर्वोत्तर राज्यों और बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में भी आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 7 दिनों के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं, मध्यप्रदेश में आज आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई।

अमेरिका दे रहा भारत पर भारी दबाव, लेकिन झुकेंगे नहीं पीएम मोदी, पुतिन की ट्रंप को दो टूक

इंटरनेशनल डेस्क । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच से भारत की संप्रभुता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व का लोहा माना है। पुतिन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अमेरिका चाहे जितना भी जोर लगा ले, वह रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर दबाव नहीं बना सकता। उन्होंने पीएम मोदी को एक ऐसा नेता बताया है जो राष्ट्रीय हितों के साथ कभी समझौता नहीं करते। रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार (4 जून 2026) को भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह सफलता भारत के लोगों की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी की बेहतरीन रणनीतियों का नतीजा है। पुतिन ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर के जादुई आंकड़े को पार कर जाएगा। पुतिन ने याद दिलाया कि भारत और रूस का रिश्ता कोई नया नहीं है, बल्कि यह 1947 में आजादी के समय से ही चला आ रहा है जब सोवियत संघ ने भारत को आगे बढ़ने में हर संभव मदद की थी। उन्होंने कहा कि आज यह स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से आगे बढ़कर फार्मास्युटिकल जैसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार कर रही है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों को दी गई प्रतिबंधों में छूट खत्म करने की धमकी दी है। अमेरिका की दलील है कि यह छूट केवल सीमित समय के लिए थी। हालांकि, भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि देश की ऊर्जा नीति का फैसला किसी विदेशी शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। पुतिन ने स्पष्ट किया कि भारत के किसी अन्य देश (जैसे अमेरिका) के साथ बढ़ते संबंधों को रूस कभी भी नकारात्मक नजरिए से नहीं देखता। उन्होंने रूस को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़े निवेशक के रूप में पेश करते हुए भविष्य के कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने की इच्छा जताई है।

ममता बनर्जी ही रहेंगी सुप्रीम लीडर- सलाहकार का पद मंजूर नहीं, तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट में भी बगावत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी के बागी खेमे में महज 24 घंटे के भीतर ही असंतोष के सुर उभर आए हैं। 58 बागी विधायकों ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक दल पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन अब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले इस बागी गुट में भारी बेचैनी देखी जा रही है। कई विधायकों ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी ही उनकी सुप्रीम लीडर रहेंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ममता बनर्जी को महज एक सलाहकार बनाकर छोड़ा गया, तो वे इस बागी गुट में रहने पर दोबारा विचार कर सकते हैं। बागी विधायक दल के नवनिर्वाचित विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद ही बागी गुट के भीतर अलग-अलग सुर दिखाई देने लगे। इससे साफ है कि बागियों के सामने अब एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वे एक तरफ पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी से दूरी बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ, वे टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी के साथ अपना राजनीतिक और भावनात्मक रिश्ता भी बनाए रखना चाहते हैं।

ममता बनर्जी पर बंटा बागी गुट

बैठक खत्म होने के बाद पांचला के बागी विधायक गुलशन मल्लिक ने पत्रकारों से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। वह सिर्फ एक सलाहकार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी पूरी तरह उनके नेतृत्व में काम करे। दरअसल, यह विवाद बुधवार को ऋतब्रत बनर्जी के एक प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ। ऋतब्रत ने सुझाव दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री को पुनर्गठित विधायक दल का मुख्य सलाहकार बनाया जाना चाहिए। गुलशन मल्लिक ने इसी पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को सर्वोच्च नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, तो हमें सोचना होगा कि हम इस गुट में रहें या नहीं। इस बयान ने विद्रोह के सबसे बड़े अंतर्विरोध को सामने ला दिया है। यह पूरा विद्रोह ममता बनर्जी के नाम पर ही किया गया है। लेकिन अब इसी बात पर बहस छिड़ गई है कि खुद ममता बनर्जी की भूमिका क्या होगी? विद्रोह करने वाले 58 विधायकों ने शुरू से ही एक बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। वे केवल ममता के भतीजे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ हैं।

सिर्फ नेतृत्व पर ही उठे सवाल

सीतई से एक और बागी विधायक संगीता रॉय बसुनिया ने भी मल्लिक की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमारी सुप्रीम लीडर हैं और हमेशा रहेंगी। वह सलाहकार नहीं हो सकतीं। वह हमारी नेता हैं। ऋतब्रत ने दरअसल ममता को सलाहकार बनाने का प्रस्ताव एक रणनीति के तहत दिया था। वह विद्रोह के राजनीतिक असर को कम करना चाहते थे। वह तृणमूल के आम कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना चाहते थे कि यह आंदोलन पार्टी सुप्रीमो के खिलाफ नहीं है। लेकिन गुरुवार को आए बयानों ने साफ कर दिया कि बागी खेमे का एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के अधिकारों को कम करने वाले किसी भी फॉर्मूले से बेहद असहज है। ममता बनर्जी ने 1998 में इस पार्टी की स्थापना की थी। वह पार्टी को विपक्ष के हाशिए से उठाकर 2011 में सत्ता तक लेकर आईं। विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में भी बागियों ने ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वे विधायक दल के कामकाज पर अभिषेक बनर्जी के अधिकार को अब स्वीकार नहीं करते हैं।

सीएम सैनी के दौरे से पहले मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी, हरियाणा बनेगा खालिस्तान भेजा ई-मेल, एजेंसियां सतर्क

कुरुक्षेत्र। खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए एक धमकी भरे ईमेल में कुरुक्षेत्र जिला के दो मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इनमें थानेसर के स्थाण्वीश्वर मंदिर में आठ जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा प्रस्तावित है। वहीं दूसरा मंदिर पिहोवा का कार्तिकेय मंदिर है। मंदिरों के नाम लिख कर भेजे गए इस तरह के ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। थाना कृष्णा गेट पुलिस की टीम के उप निरीक्षक लाभ सिंह ने डाग स्क्वायड की टीम के साथ मंदिर पहुंचकर जांच की। अब देर सायं बम स्क्वायड दस्ता पहुंचकर मंदिर परिसर में जांच पड़ताल करेगा। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन निगरानी बढ़ा दी है। खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए इस धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस ई-मेल में थानेसर के स्थाण्वीश्वर महादेव मंदिर और पिहोवा के कार्तिकेय मंदिर को उड़ाने की धमकी के साथ-साथ गुरुग्राम मेयर कार्यालय, नगर निगम कार्यालय और रेलवे ट्रैक पर भी आईईडी धमाके करने की चेतावनी दी गई है। वहीं इस तरह की धमकी को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री दौरे को देखते पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद आठ जून को सोमनाथ मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और स्थाण्वीश्वर मंदिर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

पेपर लीक पर छात्रों का हल्ला बोल, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में प्रकाश राज -सोनम वांगचुक का साथ

नई दिल्ली । देश में लगातार बढ़ रहे पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों को लेकर छात्रों में भारी गुस्सा है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने आवाज उठाई है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 जून को दिल्ली में एक शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अब इस आंदोलन को मशहूर अभिनेता प्रकाश राज और जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी साथ मिल गया है। प्रकाश राज शुरू से ही इस पार्टी का समर्थन करते आ रहे हैं और उन्होंने खुद को भी एक कॉकरोच बताया है। इस आंदोलन की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर देश के छात्रों और युवाओं से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। अभिजीत दीपके ने बताया कि वह 6 जून को अमेरिका से भारत वापस लौट रहे हैं और दिल्ली पहुंचकर खुद इस शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की कमान संभालेंगे। उनका कहना है कि पेपर लीक ने देश के लाखों होनहार छात्रों के सपनों को तोड़ दिया है, जिसके खिलाफ अब चुप बैठना मुमकिन नहीं है। इस आंदोलन को और मजबूती देते हुए अभिनेता प्रकाश राज ने सोनम वांगचुक के वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने साफ किया कि वह छात्रों के इस जरूरी आंदोलन के साथ पूरी तरह खड़े हैं। प्रकाश राज ने युवाओं से अपील करते हुए कहा, मैं 6 तारीख को दिल्ली पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि इस बेहद जरूरी आंदोलन को अपना समर्थन दे सकूं।

मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

नई दिल्ली। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में आरोपी और होटल फ्लोरिस स्टेज के मालिक लक्केश बजाज को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानु प्रताप सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। जहां साकेत कोर्ट ने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने चार दिनों की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फैसला दिया। होटल का मैनेजर जय मिश्रा अभी पुलिस की पहुंच से दूर है जिसकी तलाश की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपराज्यपाल ने इस पूरे अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरी ओर, दिल्ली सरकार ने भी मामले की तह तक जाने और जवाबदेही तय करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है, जो तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री घायलों का हालचाल जानने के लिए साकेत स्थित मैक्स अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने डॉक्टरों से बात कर घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। साकेत स्थित मैक्स अस्पताल ने गुरुवार, 4 जून को एक बयान जारी किया। अस्पताल ने बताया कि हौज रानी क्षेत्र के एक होटल में लगी आग में घायल 15 मरीज भर्ती हैं। इन सभी का उपचार चल रहा है और इनमें से 13 मरीज विदेशी नागरिक हैं। अस्पताल के बयान के अनुसार, छह मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इन सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है।

शिक्षा नहीं, राजनीति का एजेंडा..., सीबीएसई के यू-टर्न पर जयराम रमेश ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया के एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिसंबर 2025 में सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी की अर्धवार्षिक बैठक हुई थी। इस बैठक में गवर्निंग बॉडी ने विशेष तौर पर और स्पष्ट रूप से अपनी पाठ्यक्रम समिति की उस सिफारिश को मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि एनसीईआरटी द्वारा भाषाओं की ग्रेडेड टेक्स्टबुक जारी किए जाने तक सीबीएसई को अपनी मौजूदा अध्ययन व्यवस्था, विशेष रूप से भाषा संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में, जारी रखनी चाहिए। इस निर्णय पर अब तबादला किए जा चुके सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव के हस्ताक्षर भी थे। सीबीएसई के OSM सिस्टम को लागू करने में दिखाई गई अक्षमता, जल्दबाजी और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के अलावा, सीबीएसई कक्षा 9 और 10 में तीन-भाषा फॉर्मूला को मनमाने तरीके से लागू करने को लेकर भी चर्चा में है। आखिर इस फैसले की पृष्ठभूमि क्या है? लेकिन मई 2026 में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों से कहा कि वे 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा जोड़ें। इतना ही नहीं, सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया कि वे कक्षा 9 के छात्रों को तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताबों का इस्तेमाल करें। आखिर इन छह महीनों में ऐसा क्या बदल गया? एनसीईआरटी ने अब तक कक्षा 9 और 10 के लिए तीसरी भाषा की कोई पाठ्यपुस्तक जारी नहीं की है। जिस निर्णय पर हस्ताक्षर करने वाले सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी तब भी अपने पदों पर बने हुए थे, उसी दौरान सीबीएसई ने प्रभावी रूप से अपनी पाठ्यक्रम समिति की सिफारिश को पलट दिया, जबकि उसे उसकी अपनी गवर्निंग बॉडी द्वारा मंजूरी दी जा चुकी थी। आखिर सीबीएसई ने यह यू-टर्न क्यों लिया और किसके आदेश पर लिया? इस फैसले के पीछे कोई शैक्षणिक तर्क नहीं है। इससे शैक्षणिक कैलेंडर और स्कूलों की योजना व्यवस्था में अराजकता फैल रही है और लाखों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। यहां एजेंडा साफ तौर पर राजनीतिक दिखाई देता है। स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई जैसे उसके स्वायत्त संस्थान शिक्षा विशेषज्ञों की सलाह पर नहीं, बल्कि मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छाओं और एजेंडे के अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब जवाबदेही तय करने की बात आती है, तो सीबीएसई चेयरपर्सन और सचिव जैसे अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री की कैबिनेट में बैठे उनके राजनीतिक आकाओं को बचाया जाता है। मंत्री प्रधान, जिन्होंने खुद को एक ऐसे पॉलिटिकल हैक के रूप में पेश किया है, जिनमें न ईमानदारी है और न ही शैक्षणिक विशेषज्ञता के प्रति कोई सम्मान, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

आखिर सीबीएसई ने यह यू-टर्न क्यों लिया और किसके आदेश पर लिया? इस फैसले के पीछे कोई शैक्षणिक तर्क नहीं है। इससे शैक्षणिक कैलेंडर और स्कूलों की योजना व्यवस्था में अराजकता फैल रही है और लाखों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है।